ग्रोर सोनीपत लाइन की तरफ भेज देंगे । इस काम को करने के साथ साथ रिंग रेलवे द्वारा दिल्ली से दूर बसी हुई बस्तियों निवासियों को यातायात की भी सुविधा सुलभ होगी । तीन नये स्टेशंस हमार खोलने का विचार है । एक तो सफदरजं का होगा .....

ग्रध्यक्ष महोदय : जो नई बस्तियां हैं ग्रोर जहां सरकारी कर्मचारी रहते हैं ....

श्री शाहनवाज खां : जी हां मैंने फरमाया तो है कि बहुत सी बस्तियों को इससे फायदा होगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस रिंग रेलवे का टरमिनस कहां होगा, यह रुकेगी कहां पर ?

श्री शाहनवाज खां : यह हजरत निजामुद्दीन से सफदरजंग की तरफ़ से होती हुई दिल्ली छावनी से सब्जीमंडी की तरफ जायेगी ।

Shrimati Savitri Nigam: The hon. Minister just stated that after land has been acquired, it will take three to four year. What is the approximate time likely to be taken in acquiring the land?

Shri Shahnawaz Khan: I am afraid I cannot give any definite date because it depends on the land acquisition authorities, how quickly they acquire the land mainly from the defence authorities. There are certain pieces of land which come in the cantonment area. We have been in touch with them. I hope it will not be long.

Shri S. N. Chaturvedi: Why is it that in the suburban railway steam traction is preferred to electric traction inspite of the possibility of smoke nuisance in the former?

Shri Shahnawaz Khan: As I just submitted, the main idea behind this was to provide alternative lines of connection to routes for the transport of goods traffic mainly.

Shri A. P. Jain: Will it benefit the local people and ease local traffic also? Monorail being the latest type of rail for metropolitan transport, has Government given any attention to substitute this by monorail?

Shri Shahnawaz Khan: I have no doubt that the local population would benefit very considerably from it. As I explained, the main intention of providing this avoiding line is to provide facilities for the movement of goods traffic and, therefore, there is no idea of having monorails.

Shri S. C. Samanta: How many complaints about the inadequacy of compensation for acquired land had come?

Shri Shahnawaz Khan: Information is not available with the Railway Ministry because the land acquisition officer is the person who deals with it.

श्री कछवाय : जिस तरह दिल्ली की घनी बस्तियों को यह रिंग रेलवे की सुविधा दी जा रही है क्या ग्रन्य शहरों में भी इसी तरह की रेलवे सुविधा देने का विचार हो रहा है, यदि हां, तो कहां कहां ?

श्री शाहनवाज खां : वह तो ग्रलग ग्रलग जब ग्रोर जहां सवाल पैदा होता है तो उस पर फैसला किया जाता है । मिसाल के तौर पर बम्बई या कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहर हैं जहां कि यह सुविधा दी हुई है । जहां भी यह सवाल पैदा होता है वहां के लिए ग्रलहदा तौर पर विचार किया जाता है ।

दिल्ली में रेल के पुल पर यातायात

+

*५७७. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री भागवत झा ग्राजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री इ० मधुसूदन राव : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यमुना पर नावों का पुल बन जाने से रेल के पुल पर यातायात में कुछ कमी हुई है ; और

(ख) क्या इसी तरह के कुछ और पुल बनाने का भी विचार है?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय कोई और पुल बनाने का प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : दिल्ली में यमुना पर यह नावों का दूसरा पुल जो बनाया गया है जिससे दिल्ली में रेल के पुल पर यातायात में पर्याप्त सुविधा मिली है, तो क्या सरकार ने इस बात की भी कोई जानकारी ली है कि यह साल में कितने मास तक जारी रह सकेगा और जिन दिनों यह पुल नहीं रहेगा उस समय यातायात की सुविधा के लिए और क्या व्यवस्था की जायेगी?

श्री राज बहादुर : स्पष्ट है कि नावों का पुल बाढ़ के वक्त जारी नहीं रह सकता है । यह पुल नवम्बर से जून तक हर वर्ष रहेगा । इसके बनने से जो सुविधा मिली है वह यह है कि सवेरे आठ बजे से ग्यारह बजे तक और शाम को पांच बजे से आठ बजे तक जितनी साइकिल ट्रैफिक, पैडेस्ट्रियन ट्रेफिक है वह सब इस नाव के पुल से पास किया जाता है । अनुमान लगाया गया है कि लगभग ३० हजार आदमी या साइकिल जो कुछ भी हैं करीब ३० हजार आदमी इस छः घंटे के अर्से में इस पुल से गुजर कर पार होते हैं बाकी अर्से में कोई ५००० व्यक्ति पुल से पार होते हैं .....

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह था कि बाढ़ के दिनों में जब यह पुल नहीं रहेगा और ट्रेफिक का प्रेशर ज्यादा होगा तो उसके लिए क्या कोई अन्य व्यवस्था की जायेगी ?

श्री राज बहादुर : एक सवाल में कई सवाल थे और मुझे अफसोस है कि उस वक्त याद नहीं रख सका । उम्मीद की जाती है कि वजीराबाद का पुल तैयार हो जायेगा जो कि अप्रैल के आखिर तक खोल देंगे । इस के इलावा दो और पुल बन रहे हैं । एक और पुल हुमायूं के मकबरे के पास सड़क का पुल बनाया जा रहा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि वजीराबाद का पुल जैसा कि माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि अप्रैल के आखिर तक उस के खुल जाने की सम्भावना है, दूसरा पुल जो आप यमुना पर बना रहे हैं उस के कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री राज बहादुर : उस के पूरा हो जाने की उम्मीद तो जल्दी थी लेकिन अभी हाल में ऐसा हुआ कि उस जगह पर कि जहां पुल बनाया जा रहा था, जमुना का रुख कुछ बदल गया जिसकी वजह से जहां उस की बुनियादें लगानी थी और जो काम करना था उस में कुछ फर्क आया । जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था उसने अपनी कौस्ट कुछ बढ़ा कर मांगी है । यह सब सवालात जेरेगौर हैं । इस बीच में एक तरफ का एप्रोच तो बन चुका है और दूसरी तरफ का बन रहा है ।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय ने हुमायूं के मकबरे के पास जिस पुल के बनाये जाने का उल्लेख किया है, क्या मैं जान सकता हूं कि उस पुल के कब तक बन जाने की सम्भावना है?

श्री राज बहादुर : मैंने उस का जवाब दे दिया है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान, वजीराबाद और हुमायूं के मकबरे के पास जो पुल बनने वाले हैं, उस से यातायात में कुछ सुविधा मिलेगी लेकिन जो असली ट्रैफिक का प्रैशर है वह तो दिल्ली के यमुना पुल पर है तो

क्या उस पुल के किनारे को चौड़ा करने की किसी व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : उम्मीद की जाती है कि जो ट्रैफिक वर्तमान यमुन पुल पर है वह ट्रैफिक वजीराबाद और हुमायूं के मकबरे के पास बन रहे पुलों की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा और इस से दिल्ली के यमुना पुल पर ट्रैफिक का प्रैशर काफी कम हो सकेगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि परसों २४ तारिख को इतवार के दिन इस पुल पर जो पुलिस खड़ी थी उस ने सुबह आठ बजे से ले कर दो बजे तक इस नाव के नये बने हुए पुल को बंद रक्खा क्या ऐसा उसने सिर्फ अपनी पुलिस शाही दिखाने के लिए और जनता को तंग करने करने के लिए किया ?

श्री राज बहादुर : मैं नहीं समझता कि पुलिस ने बिला वजह पुल को बंद किया होगा । मेरे नोटिस में कम से कम यह चीज नहीं है ।

Prices of Agricultural Products

\+

*578. **Shri Inder J. Malhotra:**
Shri Bibhuti Mishra:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Rameshwar Prasad Singh:
Shri Heda:
Shri Bishanchaader Seth:
Shri Yashpal Singh:
Shri P. R. Patel:
Shri D. C. Sharma:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Ram Hark Yadav:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a **Board** to advise the Cabinet from time to time regarding the fixation of prices of agricultural products;

(b) if so, the details about the Board and the number of the Members thereof;

(c) whether it is also a fact that the Board will be assigned the responsibility of fixing the prices of industrial products besides the agricultural products; and

(d) when the said Board is likely to be set up and the reaction of the cultivators in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (d). No decision has been arrived at on the question of setting up an advisory committee or a Board on agricultural prices.

Shri Inder J. Malhotra: This question of price fixation for agricultural products has been under the consideration of the Government for a very long time. I would like to know the main difficulties that come in the way of reaching a decision at an early date.

Dr. Ram Subhag Singh: It is true that it is under the consideration of the Government since the 24th November, 1959 and the matter was taken up to the Cabinet in September 1962. Later on it was dropped temporarily but recently in February 1963 the panel on agriculture suggested that an advisory committee for determining the prices of agricultural commodities should be set up and it is also under examination of the Ministry whether an agricultural commodities board should be set up to regulate the wholesale prices and for supervising the activities of the wholesale and retail trade. This is under active consideration.

Shri Inder J. Malhotra: In view of the fact that such an agency does not exist at present and may not also exist in the near future, what is the procedure adopted for the fixation of prices at present?